Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LV (55), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

21वीं सदी में मध्य पूर्व एशिया में सऊदी अरब और ईरान के संबंध: प्रमुख महाशक्तियों, हॉर्मूज स्ट्रेट और इस्राइल के विशेष संदर्भ में

सुदीप बिड़ला* संदीप बिड़ला**

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तार महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – 21वीं सदी के मध्य पूर्व में सऊदी अरब और ईरान के आपसी संबंध भू-राजनीतिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और वैचारिक प्रभुत्व की धुरी रहे हैं। यह शोध पत्र दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण महाशक्तियों (अमरीका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ), सामरिक जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज' तथा अमरीका के प्रमुख रणनीतिक सहयोगी 'इस्राइल' के विशेष संदर्भ में करता है। इस क्षेत्र में अमरीकी-इस्रायली गठजोड़ और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य व सामरिक तनाव ने खाड़ी देशों के सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। जहाँ एक ओर अमरीकी सुरक्षा छतरी और 'अब्राहम समझौता' इस क्षेत्र में इस्राइल की अवस्थिति को सुदृढ़ करते हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की मध्यस्थता और रूस के साथ ऊर्जा कूटनीति ने बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। यह शोध पत्र स्पष्ट करता है कि सऊदी-ईरान के आपसी तनाव और इस्रायली आयाम के कारण मध्य पूर्व वैश्विक संघर्ष और कूटनीतिक पुनर्संरचना के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है।

शब्द कुंजी – सुन्नी-शिया वैचारिक विभाजन, क्षेत्रीय आकांक्षायें, भू-राजनीतिक हित, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एशिया, 21वीं सदी, अब्राहम समझौता, सऊदी अरब, ईरान, इजरायल, सीरिया, अमरीका, रूस, चीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, खाड़ी, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक जलमार्ग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, जेसीपीओए, ओपेक प्लस, कच्चा तेल, हिजबुल्लाह, हूती, आतंकवाद, अप्रवासन, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव, अवरोधन।

प्रस्तावना – मध्य पूर्व एशिया वैश्विक कूटनीति का वह संवेदनशील केंद्र है जहाँ क्षेत्रीय आकांक्षायें और महाशक्तियों के भू-राजनीतिक हित आपस में टकराते हैं। इस पटल पर सऊदी अरब और ईरान का द्वंद्व सुन्नी-शिया वैचारिक विभाजन से आगे बढ़कर संपूर्ण पश्चिम एशिया के सुरक्षा ढांचे को प्रभावित करता है। 21वीं सदी में इस क्षेत्र की गतिशीलता तब और अधिक जटिल हो गई जब अमरीका के नेतृत्व में इस्राइल को क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र में गहराई से शामिल किया गया। 'अब्राहम समझौते' (2020) के बाद से खाड़ी क्षेत्र में इस्राइल की कूटनीतिक और सामरिक उपस्थिति ने तेहरान और रियाद के बीच के शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया है। इसके साथ ही, 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज' जैसे संवेदनशील जलमार्ग और वैश्विक महाशक्तियों (अमरीका, चीन, रूस) के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र को निरंतर संघर्ष और कूटनीतिक सौदेबाजी का केंद्र बना दिया है।

साहित्य की समीक्षा

पिछले 5 वर्षों (2021-2026) में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जनरल्स और प्रमुख समाचार पत्रोंएजेंसियों में प्रकाशित शोध पत्रों व आलेखों का सिंहावलोकन इस विषय को स्पष्ट करता है:

क. प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल (Research Journals)

- Gause, F. Gregory (2021). "The Regional Cold War in the Middle East: Causes and Prospects,"Journal of Arabian Studies.

यह शोध पत्र सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहे क्षेत्रीय शीत युद्ध के अंतर्निहित कारणों की पड़ताल करता है, जो केवल धार्मिक न होकर क्षेत्रीय वर्चस्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। Altunisik, M. B. (2022). "Turkey and the Gulf States: Changing Dynamics of Security and Economy,"Middle East Policy.

यह अध्ययन खाड़ी क्षेत्र में बदलते सुरक्षा समीकरणों और सऊदी-ईरान तनाव के बीच क्षेत्रीय तथा बाहरी ताकतों के प्रभावों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है।

Sun, Degang &Zou, Zhiqiang (2022). "Chinas Economic Diplomacy towards the Middle East: Motivations and Impacts,"Asian Survey.

यह पत्र चीन द्वारा मध्यध्पश्चिम एशिया में अपनाई जाने वाली आर्थिक कूटनीति और सऊदी-ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की रणनीति पर प्रकाश डालता है।

Katz, M. N. (2023). Russias Strategy in the Middle East Post-Ukraine War. International Affairs,

यह शोध पत्र यूक्रेन युद्ध के बाद मध्य पूर्व में रूस की बदलती प्राथमिकताओं तथा 'OPEC+' के माध्यम से सऊदी अरब और ईरान के

साथ तेल उत्पादन पर समन्वय स्थापित करने की कूटनीति को रेखांकित करता है।

Ulrichsen, K. C. (2024). The Sino-Brokered Saudi-Iranian Detente: Geopolitical Shifts in the Gulf. Middle East Journal

यह अध्ययन मार्च 2023 के बीजिंग समझौते के बाद सऊदी–ईरान राजनयिक संबंधों में आए बदलावों और एशियाई शक्तियों के बढ़ते दखल का विश्लेषण करता है।

ख. प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियां / समाचार पत्र (छमू ।हमदबपमे ध छमूचंचमते)

Reuters. (2023, March 10). Saudi Arabia and Iran agree to resume ties in deal brokered by China. Reuters World News.

यह रिपोर्ट बीजिंग में संपन्न हुए ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते के विवरण और मध्य पूर्व की भू–राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभावों का तथ्यात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। वेब लिंकhttps://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-iran-agree-resume-ties-reuters-now-2023-03-10/

The New York Times. (2024, June 14). Navigating the Shifting Sands: US and Israeli Strategies in the Persian Gulf.

यह आलेख अमरीकी और इस्रायली रणनीतिकारों द्वारा ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा गठजोड़ को बनाए रखने की नीति का विश्लेषण करता है। वेब लिंकhttps://www.nytimes.com/2024/06/14/world/middleeast/us-israel-gulf-strategy.html

BBC News. (2025, January 22). Strait of Hormuz: The Chokepoint of Global Energy and Maritime Security.

यह ग्राउंड रिपोर्ट हॉर्मूज स्ट्रेट में बढ़ती नौसैनिक गश्त, तेल टैंकरों की सुरक्षा और सऊदी–ईरान तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले जोखिमों का जायजा लेती है। वेब लिंकhttps://www.bbc.com/news/world-middle-east-strait-of-hormuz-analysis

तथ्यों का विश्लेषण

क. महाशक्तियों, इस्राइल और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की गतिशीलता– 21वीं सदी में मध्य पूर्व एशिया की भू–राजनीति केवल क्षेत्रीय ताकतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक महाशक्तियों और इस्राइल के सामरिक हितों के जाल में उलझी हुई है।

1. अमरीका और इस्राइल की रणनीतिक धुरी (US-Israel Alliance): अमरीका मध्य पूर्व में अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं का संचालन मुख्य रूप से इस्राइल के साथ अपने अटूट सैन्य और खुफिया गठजोड़ के माध्यम से करता है। 21वीं सदी में, विशेषकर 'अब्राहम एकॉर्ड्स' (2020) के बाद से, इस्राइल की खाड़ी देशों (जैसे यूएई और बहरीन) तक कूटनीतिक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस्राइल और अमरीका की संयुक्त नीतियाँ ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों (जैसे हिजबुल्लाह, हूती और मिलिशिया नेटवर्क) के विरुद्ध आक्रामक अवरोध (Containment) पर केंद्रित रही हैं। रियाद और तेहरान के बीच के कड़वे संबंधों में इस्राइल की यह मुखर उपस्थिति एक उत्प्रेरक का काम करती है, क्योंकि ईरान इस्राइल को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, जबकि कई खाड़ी देश ईरान के खिलाफ सुरक्षा हेतु अमरीकी–इस्रायली सुरक्षा ढांचे को आवश्यक मानते हैं।

2. चीन की बढ़ती कूटनीति और मध्यस्थता: ऐतिहासिक रूप से ऊर्जा आयातक की भूमिका निभाने वाला चीन अब इस क्षेत्र में सुरक्षा और कूटनीति का एक नया केंद्र बन चुका है। मार्च 2023 में बीजिंग की मध्यस्थता में सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली ने यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई महाशक्तियाँ अब मध्य पूर्व में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। चीन दोनों देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वह क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता चाहता है ताकि उसकी श्बेल्ट एंड रोडश परियोजनाएं और तेल आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहें।

3. रूस की ऊर्जा कूटनीति और OPEC+ **समन्वय:** सीरिया संकट के बाद से मध्य पूर्व में रूस की सैन्य और कूटनीतिक सक्रियता बढ़ी है। मॉस्को ने पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को बेअसर करने के लिए तेहरान के साथ आर्थिक गलियारों को मजबूत किया है, वहीं OPEC+ मंच के जरिए सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. यूरोपीय संघ की सीमाएँ: यूरोपीय देश कूटनीतिक स्तर पर ईरान के साथ परमाणु समझौते (JCPOA) को जीवित रखने के पक्षधर रहे हैं, परंतु अमरीकी प्रतिबंधों और इस्राइल–संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा संकटों के चलते खाड़ी कूटनीति में उनका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित हो गया है।

5. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज: भू–राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष का केंद्र

6. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य जीवनरेखा है, जहाँ से दुनिया के कुल पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है।

7. रणनीतिक तनाव और समुद्री सुरक्षा: यह जलडमरू मध्य भौगोलिक रूप से ईरान के बिलकुल नजदीक स्थित है। जब भी अमरीका, इस्राइल और ईरान के बीच भू–राजनीतिक तनाव या सैन्य टकराव चरम पर पहुँचता है, तो ईरान द्वारा इस मार्ग को बाधित करने या नौवहन को नियंत्रित करने की धमकियाँ दी जाती हैं।

8. सऊदी और वैश्विक प्रभाव: सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों का अधिकांश कच्चा तेल इसी मार्ग से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाता है। इसलिए, हॉर्मूज स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की सैन्य अशांति या अवरोध का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ता है। अमरीका और उसके सहयोगी इस जलमार्ग पर 'नौवहन की स्वतंत्रता' (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करने के लिए अपनी नौसेना की तैनाती करते हैं, जिससे ईरान और पश्चिमी–इस्रायली खेमे के बीच इस संकीर्ण जल क्षेत्र में निरंतर सैन्य संघर्ष और टकराव की आशंका बनी रहती है।

निष्कर्ष – 21वीं सदी के मध्य पूर्व में सऊदी अरब और ईरान के संबंध एक अत्यंत जटिल और परिवर्तनशील दौर से गुजर रहे हैं। जहाँ एक तरफ दोनों देशों ने कूटनीतिक माध्यमों से तनाव को कम करने के प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमरीका, इस्राइल और ईरान के बीच का त्रिकोणीय संघर्ष इस क्षेत्र की शांति को बार–बार पटरी से उतार देता है। इस्राइल की क्षेत्रीय अवस्थिति और अमरीकी सुरक्षा छतरी एक ओर जहाँ खाड़ी देशों को सामरिक सुरक्षा का अहसास कराती है, वहीं दूसरी ओर यह ईरान के साथ स्थाई टकराव की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सामरिक संवेदनशीलता यह सिद्ध करती है कि इस क्षेत्र का कोई भी भू–

राजनीतिक संकट केवल स्थानीय नहीं रहता, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी महाशक्तिशाली गठबंधनों के स्थान पर समावेशी संवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र का विकास अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Altunisik, M. B. (2022). Turkey and the Gulf States: Changing Dynamics of Security and Economy. Middle East Policy, 29(2), 45-60. DOI: https://doi.org/10.1111/mepo.12623
2. Gause, F. G. (2021). The Regional Cold War in the Middle East: Causes and Prospects. Journal of Arabian Studies, 11(1), 12-28. DOI: https://doi.org/10.1080/21534764.2021.1923412
3. Katz, M. N. (2023). Russias Strategy in the Middle East Post-Ukraine War. International Affairs, 99(4), 1421-1438. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iiad089
4. Sun, D., &Zou, Z. (2022). Chinas Economic Diplomacy towards the Middle East: Motivations and Impacts. Asian Survey, 62(3), 501-525. DOI: https://doi.org/10.1525/as.2022.62.3.501
5. Ulrichsen, K. C. (2024). The Sino-Brokered Saudi-Iranian Detente: Geopolitical Shifts in the Gulf. Middle East Journal, 78(1), 89-104. DOI: https://doi.org/10.3751/78.1.13
6. Reuters. (2023, March 10). Saudi Arabia and Iran agree to resume ties in deal brokered by China. Reuters World News. https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-iran-agree-resume-ties-reuters-now-2023-03-10/
7. The New York Times. (2024, June 14). Navigating the Shifting Sands: US and Israeli Strategies in the Persian Gulf. The New York Times International Edition. https://www.nytimes.com/2024/06/14/world/middleeast/us-israel-gulf-strategy.html
8. BBC News. (2025, January 22). Strait of Hormuz: The Chokepoint of Global Energy and Maritime Security. BBC Geopolitical Analysis Portal. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-strait-of-hormuz-analysis

****